Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 1, January-2019, ISSN 2230-7540

गंडक परियोजना के एतिहासिक वर्णन

Dr. Ajay Kumar Jha*

Village - Dabhari, Post – Bhoud, District - Madhubani

सार – *मिथिला के भौगोलिक परिक्षेत्रा में नदी श्रृंखलाओं का जाल फैला हुआ है। मिथिला की बस्तियाँ, कस्बे और शहर आम तौर पर नदियों के तटों पर ही बसे हुये हैं। यही कारण है कि ऐतिहासिक काल में यह भू-भाग मिथिला के अतिरिक्त तिरभुक्ति अथवा तिरहुत के नाम से भी विख्यात रहा है। पूरब से पश्चिम की ओर मिथिला में लगभग* 15 *प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जिनकी असंख्य सहायक नदियाँ हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में छारण कहा जाता है। इस नदी-मातृक भू-भाग का आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक अभ्युत्थान मुख्यतः बाढ़ नियंत्राण, सिंचाई की अत्याधुनिक व्यवस्था, जल विद्युत के समुचित विकास, सहायक उद्योगों की स्थापना तथा उनकी अत्याधुनिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन गंगा के उत्तरी किनारे से लेकर हिमालय की तराई तक चैड़ा और पश्चिम चम्पारण से लेकर कटिहार तक लम्बा लगभग* 58.500 *किमी*0 *के विस्तृत भू-भग में फैला हुआ गंगा घाटी का यह मैदान देश का सबसे बड़ा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रा है। इसका औसतन* 76% *क्षेत्राफल प्रत्येक वर्ष बाढ़ में डूब जाता है, जो बिहार के कुल क्षेत्राफल का* 40% *हिस्सा है। देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रा की कुल आबादी के* 56% *लोग इस इलाके में बसते हैं*1 *बाढ़ की विभिषिका के दंस को भोगने के अभिशप्त इस इलाके में मध्य काल से ही जहाँ-तहाँ तटबंधों का निर्माण किया जाने लगा था।* 1897 *में पहली बार कलकत्ता में बाढ़ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कोसी नदी को नियंत्रित करने के लिये गम्भीरता पूर्वक विचार हुआ*2*। यहीं से बाढ़ पर बहस की दौर प्रारम्भ हुई, और इसे नियंत्रित करने के लिये तात्कालिक उपाय के रूप में तटबंधों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। लेकिन परियोजना तैयार कर मिथिला के भू-भागों को बाढ़ से मुक्त करने के लिये आजादी से पहले कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा सके। आजादी के बाद सरकार ने इस ज्वलंत समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना प्रारम्भ किया जिसके परिणाम स्वरूप कोसी, गंडक, बागमती और कमला एवं महानन्दा नदी परियोजनाओं के अतिरिक्त कई अन्य छोटी-छोटी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, ताकि न केवल मिथिला के लोगों को बाढ़ से मुक्ति ही नहीं मिल सके, बल्कि सिंचाई के कारगर व्यवस्था द्वारा कृषि के समुन्नत और जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उद्योगों को विकसित किया जा सके।*

----------X----------

गंडक-परियोजना:

पश्चिम चम्पारण के भैंसालोटन में गंडक नदी मिथिलांचल में प्रवेश करती है। इस नदी का उद्गम स्थल हिमालय के केन्द्रीय भाग से पश्चिम में धौलागिरी शिखर और पूर्व में मन्ना तथा रसुवागढ़ी की चोआ के बीच 14612 वर्ग फीट समप्रसार क्षेत्रा है। यह नारायणी, शालग्रामी और सदानीरा के नाम से भी जानी जाती है। इस नदी में 7 धारायें हैं। इसलिए इसे सप्त गंडकी भी कहा जाता है। सोमेश्वर पहाड़ के पश्चिमी भाग से होकर यह नदी मैदान में प्रवेश करती है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है।[20] यह नदी मिथिला और नेपाल और मिथिला तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का भी काम करती है। मिथिला में भैंसालोटन अर्थात बाल्मिकी नगर से कुछ दूर पश्चिम जाकर गंडक दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। प्रथम मोड़ से लगभग 11.50 मील तक गंडक का दायाँ तट जहाँ नेपाल की भूमि से सटता है, वहीं पूर्वी तट मिथिला के पश्चिमी जिला से। इस प्रकार 11.50 मील तक मिथिला और नेपाल की सीमा बनने के बाद यह नदी उत्तरप्रदेश और मिथिला की सीमा रेखा बनकर बहती है। यहाँ से हाजीपुर में गंगा में समाहित होने तक गंडक का प्रवाह मार्ग 170 मील है जो पूर्व/दक्षिण कोण में प्रवाहित होती है। ग्लेशियर के प्रभाव से इस नदी का बहाव 10 घन फीट प्रति सेकेण्ड से लेकर 7 लाख घन फीट तक होता है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्रा नेपाल तराई में 46.5 वर्ग किमी0 है। जबकि मिथिला और गोपालगंज में 7620 वर्ग किमी0 है। कुल मिलाकर बाल्मिकी नगर से सोनपुर तक गंडक नदी का प्रवाह मार्ग 277 किमी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्रा 37407 वर्ग किमी है।[21] गंडक घाटी में मही, गंडकी, खाता, नुनु, घरहो, तेल, सोन, झाझा, बाया, हाणि, जमुआरी आदि छोटी-बड़ी लगभग 40 नदी जल उपधारायें समाहित होती हैं। गंडक नदी में भी धारा परिवर्तन की वृत्ति रही है और विशाल जल ग्रहण क्षेत्रा होने के कारण वर्षा के मौसम में यह प्रचंड बाढ़ का कारण भी

www.ignited.in

बनती रही है। इस नदी को बाँधने के लिए सबसे पहले बंगाल के नवाब अलीवर्दी खाँ के सूबेदार मीर कासिम ने तटबंध बनाने का प्रयास किया। मीर कासिम ने इस तटबंध के निर्माण पर लगभग 1 लाख रूपया व्यय भी किया, लेकिन राजनैतिक अस्थिरता के कारण तटबंध निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका। बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी हासिल की और 1769 में उसने मीर कासिम द्वारा प्रारम्भ कराये गये तटबंध निर्माण कार्य को पूरा करवाया, जिस पर हुये व्यय की वसूली स्थानीय जनता से की गयी।22 1824 और 1832 में गंडक नदी में भीषण बाढ़ आयी जिसके कारण गंडक नदी का पश्चिमी तटबंध अनेक स्थानों पर ध्वस्त हो गया। 1834 में स्थानीय स्तर पर धन की व्यवस्था कर चम्पारण जिला बोर्ड ने तटबंध के मरम्मती का कार्य पूरा किया।23 1871 और 1877 में भी बाढ़ के कारण तटबंधों का बड़े पैमाने पर मरम्मत कराना पड़ा। उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर गंडक की बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित होती थी, बार-बार सैकड़ों गाँव उजड़ने और बसने के लिए मजबूर होते थे, वहीं तटबंधों के मरम्मत पर भारी खर्चा भी होता था, जिसके व्यय का वहन स्थानीय आबादी को करना पड़ता था। बाढ़ के प्रकोप के अतिरिक्त जब सूखाड़ की स्थिति होती थी तो गंडक नदी के जल का उपयोग नहीं हो पाता था। 1873-74 में उत्तर बिहार में भीषण अकाल पड़ा। सरकार ने उस दौरान सारण तथा चम्पारण जिला में क्रमशः सारण नहर या तियुर नहर के निर्माण की योजना बनायी। तियुर अथवा त्रिवेणी नहर से 1909 में सिंचाई कार्य प्रारम्भ हो गया। किंतु नहर निर्माण का कार्य 1913 में सम्पन्न हुआ। इस नहर निर्माण में एक तकनीकी निर्माण में भयंकर गलती हो चुकी थी। यह नहर भैंसालोटन से सीधे पुरब की दिशा में निकाली गयी थी, जबकि चम्पारण में भूमि की ढ़ाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। परिणामतः उत्तर से बहता हुआ जल वर्षा के दिनों में नहर को जहाँ-तहाँ तोड़ डालता था।21 नहर को दुरूस्त करने के लिये इस तरह प्रतिवर्ष प्रयास करनेकी जरूरत थी, जो प्रायः नही हो पाता था। फलतः जब नहर से सिंचाई की जरूरत होती थी तो टूटे रहने के कारण किसानों को इस नहर से जल उपलब्ध नहीं होता था। इस नहर की हालत इतनी बदतर हो गयी कि चम्पारण के जमींदार और निलहे कोठीवाल इसके मरम्मत और रख-रखाव के लिये सरकार को धन देने के लिये तैयार हुये। किंतु सिंचाई विभाग की उदासीनता के कारण त्रिवेणी नहर से अपेक्षित लाभ स्थानीय किसानों को कभी नहीं मिल सका।

1946 ई0 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय सरकार के अन्तरिम मंत्रिमण्डल में खाद्य एवं कृषि मंत्रीबने। उन्होंने चम्पारण, मुजफ्फरपुर और सारण जिला में सिंचाई कार्य पर विशेष ध्यान दिया। गंडक नदी से सिंचाई की सम्भावना हेतु बिहार सरकार ने एक परियोजना प्रस्तावित की। परन्तु इसका विरोध उत्तर-प्रदेश की सरकार ने किया। परिणामतः गंडक परियोजना को तत्काल क्रियान्वित नहीं किया जा सका था। 1954 में 31.94 करोड़ की लागत वाली नयी गंडक परियोजना तैयार की गई।[26] 1956 में इस परियोजना के अन्तर्गत भैंसालोटन में बराज बनाने का निश्चय किया गया। इसी वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच गंडक परियोजना पर समझौता हुआ। 4 नवम्बर 1959 को गंडक परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये भारत और नेपाल सरकार के बीच समझौता किया गया। इस बीच डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रारम्भ करवाये गये सर्वेक्षण का कार्य चलता रहा। परियोजना के प्राक्कलन, सर्वेक्षण और तैयारी का कार्य लगभग 17 वर्षों अर्थात 1964 तक मंथर गति से चलता रहा। अन्ततः 4 मई 1964 को नेपाल के तत्कालिन महाराजाधिराज महेन्द्र ने भैंसालोटन अर्थात बाल्मिकी नगर में गंडक परियोजना का विधिवत् उद्घाटन किया और बराज के शिलान्यास के साथ परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ।27

इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जाना था[18]-

1. गंडक नदी के मिथिला में प्रवेश स्थल भैंसालोटन में बराज का निर्माण

2. 200 किमी0 मुख्य प0 नहर का निर्माण, जिसका 19 किमी नेपाल में 112 किमी0 उत्तर प्रदेश में और 36 किमी हिस्सा मिथिलांचल में निर्माण किया जाना था। बराज से इस नहर में 18800 क्यूसेक जलस्राव होता था, जिससे नेपाल के भैरवा जिला में 0.11 लाख हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिला में 3.78 लाख हेक्टेयर तथा गोपालगंज, सिवान, सारण और पश्चिमी चम्पारण जिला में 4.00 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की गयी थी। इस मुख्य नहर से सात शाखा नहरों के निर्माण की योजना भी प्रस्तावित की गयी थी।

3. मुख्य पूर्वी नहर की लम्बाई 283 किमी नियोजित की गई थी, जिसमें 15645 क्यूसेक जलस्राव होना था। इस नहर की भी 8 शाखायें निर्मित की जानी थी, जिनसे पश्चिम और पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिला के 5.44 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती थी।

4. नेपाल में पूर्वी तथा पश्चिमी दो नहरों का

www.ignited.in

निर्माण किया जाना था, जिनकी लम्बाई लगभग 97 किमी और 34 किमी होती।

5. गंडक से जलाप्लावित होने वाले चैरों से जल निकासी की व्यवस्था भी परियोजना में शामिल थी। ऐसे चैरों की संख्या 43 आँकी गयी थी, जिनसे जल निकास वाहिका का निर्माण किया जाना था

6. पुरानी त्रिवेणी नहर के आधुनीकीकरण और गंडक नहर में आत्मसातीकरण का प्रावधान इस परियोजना में किया गया था।

7. 907 किमी0 सिकहसा नहर का निर्माण

8. भैंसालोटन के अलावे नेपाल तराई स्थित सूरजपुरा में 15 मेगावाट जल विद्युत केन्द्र की स्थापना परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी थी।

9. नेपाल में सीमित नौका संचालन की सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना शामिल की गयी थी।

1964 में त्रिवेणी नहर के मुख्य निकास स्थल से लगभग 800 मीटर नीचे भैंसालोटन में गंडक नदी पर 739.14 मीटर लम्बे बराज का निर्माण-प्रारंभ हुआ। जो 1969-70 में पूरा हुआ। बराज का जल निकास द्वार 60 फुट है। पूरी परियोजना पर कुल 40.47 करोड़ रूपया खर्च किया जाना था, जिसमें 1985 तक 365.59 करोड़ रूपया व्यय हुआ। बराज और तटबंध का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन नहरों की निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका। बराज के ऊपर नदी के पश्चिमी किनारे से मुख्य पश्चिमी नहर का निर्माण किया गया, जिसका 23 किमी0 भाग नेपाल तराई में पड़ता है और झुलनी पूल के निकट भारत की सीमा में यह नहर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है। यहाँ नहर को दो-हिस्सों से बाँटकर नहर शृंखला का निर्माण किया गया है, जिसकी देवरिया शाखा नहर गोपालगंज में प्रवेश करती है और यहाँ से इस नहर का नाम शरण मुख्य नहर है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 161 किमी लम्बी है, जिससे गोपालगंज, सिवान और छपरा जिला के अन्तर्गत 14.08 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए जल आपूर्त्ति होती है।[29]

मुख्य पूर्वी नहर गंडक नदी के बाँयें छोड़ से निकलती है। निकास स्थल से 1.83 किमी0 की दूरी पर से दोनो नहर शाखा निकाला गया है। यहीं से एक दूसरी शाखा तिरहुत मुख्य नहर बनायी गयी है, जो 165 किमी0 लम्बी है। इससे 16.95 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है। इस नहर की जल बहाव क्षमता 15 हजार क्यूसेक है।[30] इस नहर शृंख्लाओं को 1966 तक पूरा कर लिया जाना था। लेकिन 1985 तक भी नहर शृंखला का पूरा निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं हो सका।

गंडक परियोजना की अनेक खामियाँ इसके निर्माण के समय ही दिखाई पड़ने लगी थीं। बाँध और तटबंध का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया किंतु नहर निर्माण कार्य कई स्थानों पर अभी भी अधूरा ही है। इस परियोजना की मूल समस्या जल जमाव और जल निकासी और जल ग्रहण क्षेत्रा में वृक्षारोपण की है। तटबंधों के बाहर अनेक जल जमाव क्षेत्रा बन चुके हैं और जल वितरण प्रणाली का समुचित रख-रखाव नहीं हो पाने के कारण किसानों के लिये यह बहुत लाभदायी नहीं रह गया है। गाद जमा होने के कारण मुख्य एवं शाखा नहरों से पानी आस-पास के क्षेत्रों में छितरा जाती है। 1885 में योजना आयोग ने गंडक परियोजना के निर्माण कार्य को रोक दिया। परिणामस्वरूप मिथिला में 11 लाख 52 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई लक्ष्य के स्थान पर मात्रा 8 लाख 96 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकी।31 1985 तक गंडक पूर्वी नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता 5 लाख 76 हजार हेक्टर थी। लेकिन नहरों में गाद जमने और जल जमाव के कारण यह घटकर 2 लाख 26 हजार रह गयी है।[32] सिंचाई क्षमता की पुनस्र्थापना के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत अभी कार्य किया जा रहा है। इसे 2008 में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

जाहिर है कि नियोजित प्रबंधन के अभाव में आंशिक रूप से भी क्रियान्वित गंडक परियोजना से अपेक्षित लाभ हासिल नहीं हो सका। विशेष तौर पर मिथिला परिक्षेत्रा में गंडक परियोजना सरकारी उदासीनता और समुचित रखरखाव के अभाव में अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही है।

संदर्भ

1. नरेन्द्र झा, मिथिलाक आर्थिक विकास, पटना, 2000, पृ0 15

2. दिनेश कुमार मिश्र, बन्दिनी महानन्दा, पटना, 1994, पृ0 45

3. ललितेश्वर मलिक, कोसी, 1953, पृ0 162-65

4- F.A. Sillingford (1985). "Changes in the Course of Kosi River and the Probable Dangers of Kosi River and the Probable

www.ignited.in

Dangers Arising from Them", JASB, Vol. LXIV (1), pp. 2-25

5- Robert Montgomery Martin, The History, Antiquities, Topography and Statics of Eastern India, Rangpur, 1838, pp. 395-99

6- O'Mallery, Bengal District Gazetteers, Calcutta, 1911, p. 8

7. P.C. Roy Choudhary, Bihar District Gazetters, Sahrsa 1965, p. 41-42

8. दिनेश कुमार मिश्र, पूर्वोक्त, पृ0 53-54

9. उपर्युक्त

10. उपर्युक्त

11. उपर्युक्त

12. नरेन्द्र झा, मिथिला में जल संसाधन ओ प्रबंधन, पटना, 2006, पृ0 58

13. उपर्युक्त, पृ0 59

14. उपर्युक्त, पृ0 60

15. उपर्युक्त, पृ0 61-62

Corresponding Author

Dr. Ajay Kumar Jha*

Village - Dabhari, Post – Bhoud, District - Madhubani